नई शिक्षा नीति 2020 : भाषायी प्रावधान

*डॉ. बाबू लाल बुनकर

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसका लक्ष्य देश का विश्वस्तरीय (World Class) और कौशल आधारित (Skill Based) शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा विकास (United nations Global Education Development for Sustainable Development) (SDG4) Goal4 एंजेडा को अपनाया है, जिसके तहत भारत समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को 2030 तक पूर्ण रूप से लागू करना चाह रहा हैं।

भारत में SDG4 ग्लोबल एजेंडा में विश्वस्तरीय और उच्च गुणवत्ता शिक्षा सभी को देने का लक्ष्य हैं। इसके साथ–साथ सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढावा देना है। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित (Re-Structure) और पुनः पुष्टि (Re-Confiqure) करना अनिवार्य हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' (National Education Policy-2020) को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986' को प्रतिस्थापित करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए यह बदलाव निम्न हैः–

प्रमुख बिन्दुः–

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दो पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)–2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र परदेश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया हैं।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2+3 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गयी है।
- तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग की बढावा देने की बात कही गई।
- केबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of human Resource Development-MHRD) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई हैं। इसका उद्देश्य 'शिक्षा और सीखने' (Education & learning) पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव अगर हम शिक्षकों पर देखे तो वो इस प्रकार होगा कि बच्चों का मार्गदर्शन सही दिशा में हो और स्कूलों में केवल योग्य शिक्षक ही कार्य करे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइन्स जारी की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक स्कूल में शिक्षक के पद के लिए आवेदको को 4 साल का एकीकृत बी.एड. कोर्स पूरा करना होगा।
- उच्च शिक्षा के अंतर्गत हम यह देख पायेगें कि स्नातक की डिग्री 4 साल की रहेगी जैसा कि निर्धारित किया गया है, यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बडा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है तो रिसर्च की डिग्री दी जाएगी।
- Research/Teaching Intensive विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। हर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षो में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सकें।

नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय–

केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। शिक्षा नीति में जहाँ नर्सरी से लेकर इंटर तक की शिक्षा और व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है वहीं पर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा संसाधन नहीं, बल्कि मानव के विकास का माध्यम माना गया है। स्वदेशी, स्वावलंबन, संस्कार, सुचिता, सेवा और साधना सभी को सम्मिलित करके इसे अद्यतन की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है। विदेशी भाषा को स्वैच्छिक बना दिया गया है और कक्षा पाँचवी तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे जहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करने में सहायता मिलेगी, वहीं पर फ्रेंच, चाइनीज और अन्य विदेशी भाषाओं को भी पढ़ने पर बल दिया गया है। स्पष्ट है, अंग्रेजी का विकल्प पाठ्यक्रम में मजबूती के साथ सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। एक ओर जहाँ शिक्षा को तार्किक, प्रासंगिक, उपयोगी, मौलिक और नवीन बनाया गया है, वहीं पर बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने और उसे महत्वपूर्ण बनाने की ओर ध्यान दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में तीन भाषाओं को छात्र को सीखने के लिए अनिवार्य किया गया है। आँचलिक, मातृभाषा और एक विदेशी भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दूर दृष्टि का परिचय दिया गया है। साथ ही, भारतीय भाषाओं को सीखने–सिखाने और उन्हें महत्वपूर्ण मानने पर बल दिया गया है। शिक्षा के लिए भाषा आधार है। भाषा को लेकर नई शिक्षा नीति में स्वदेशी को बढावा देने पर बल देना, इस बात का द्योतक है कि देश का गौरव स्वदेशी में ही निहित है। बढ़ती तकनीक और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर' के उपयोग को अनिवार्य बनाना भी आधुनिकता की आवश्यकता के साथ पुरातन को समझने की आवश्यकता में सामंजस्य बिठाने का प्रयास भी कम सराहनीय नहीं है।

भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षणः

- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- NEP–2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' IITI, 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' [National Institute (or Institutes) for

Pali] Persian and Prakrit, स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषाध स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकनः

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' NCERT द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी।
- NEP–2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
- NEP–2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP–2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसमें मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिये जाएगा–
  - 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट)
  - 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा
  - 3 वर्ष के बाद डिग्री
  - 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकते हैं।नई शिक्षा नीति के तहत एम फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

भारत उच्च शिक्षा आयोग

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग

(Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानोंधनिकायों का निर्धारण किया गया है–

- विनियमन हेतु– National Higher Education Regulatory Council– NHERC
- मानक निर्धारण– General Education Council– GEC
- वित पोषण– Higher Education Grants Council–HEGC
- प्रत्यायन– National Accreditation Council– NAC

नवीन शिक्षा नीति के पूर्व शैक्षणिक परिदृश्य

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से पूर्व भारत में 1986 की शिक्षा नीति संचालित थी जिसमें केवल किताबी बातों पर ध्यान दिया जाता था पुराने शिक्षा नीति में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था की स्कूल मैं कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अर्जित किया गया ज्ञान भविष्य में कैसे रोजगार सृजन में सहायक होगा। पुराने शिक्षा नीति पाठ्यक्रम प्रधान थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता था। बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने लिखने हेतु विवश किया जाता था, जिस कारण बच्चा अपनी मातृभाषा से अनभिज्ञ बना रहा। पहले उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यदि किसी कारणवश बच्चा 1 या 2 साल बाद पढ़ाई बीच में छोड़ता था तो उसका नुकसान होता था। 1 या 2 वर्षों में उसने जो कुछ भी सीखा उसका कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता था जिसके कारण पुनः डिग्री करने के लिए उसे अपने साल बर्बाद करने पड़ते थे। पहले कंप्यूटर या तकनीकी ज्ञान का अभाव था, बच्चा उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर कोडिंग का ज्ञान लेता था किंतु अब छठी कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। NEP–2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणालीधविधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहले कॉलेज से 3 साल की डिग्री लेने के बाद 2 वर्ष स्नातकोत्तर और फिर 2 वर्ष का एमफिल उसके बाद 5 वर्ष पीएचडी करने के बाद शोध उपाधि प्राप्त हो पाती थी। किंतु अब एम फिल को समाप्त कर दिया है।

नई शिक्षा

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 में, भाषा एक नकारात्मक कारक है क्योंकि भारत में एक समस्याग्रस्त शिक्षक से छात्र अनुपात है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा की शुरूआत एक समस्या है। कभी–कभी एक सक्षम शिक्षक ढूंढना एक समस्या बन जाता है और अब NEP 2020 की शुरुआत के साथ एक और चुनौती आती है, जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषा में लाता है।
2. 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के अनुसार, जो छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उन्हें चार साल की पढ़ाई करनी होगी, जबकि कोई भी आसानी से दो साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकता है। यह छात्र को पाठ्यक्रम को आधा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत कम उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है क्योंकि इससे अंग्रेजी में संवाद करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी और इस प्रकार समाज के वर्गों के बीच की खाई को चौड़ा किया जा सकेगा।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम

- नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा।

- इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा।
- छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्र किताबी और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
- कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी।

2020 में नई शिक्षा नीति 30 वर्षों के बाद आई और भारत की मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली को अकादमिक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर बनाने के उद्देश्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2040 तक एनईपी की स्थापना करना है। लक्षित वर्ष तक, योजना का मुख्य बिंदु एक–एक करके लागू किया जाना है। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधार केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगा। कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर के मंत्रालयों के साथ विषयवार समितियों का गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष

यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे य साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें। नई शिक्षा नीति में उन सभी बातों को भी सम्मिलित किया गया है जो लेख में मैंने लिखा है।

समय की आवश्यकता और भारतीयता को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए नई शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारी तभी होगी, जब प्रत्येक भारतीय भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करना सीख लेगा।

***प्राचार्य**
(भूगोल एवं समाजशास्त्र)
टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, मानव संसाधन विकास संसाधन विकास (शिक्षा) मंत्रालय भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रोग्राम ऑन एक्शन अध्याय : लेग्वेज डवलपमेंट अनुच्छेद–10
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा 2019
4. ncte-gov.in (भारत सरकार का एक सविधिक निकाय)
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) अध्याय 15, पेज नंबर 70
6. http://www.educationjournal.ort